रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259345
CG-DL-E-11122024-259345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4965] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946
No. 4965] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5364(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 4 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाएं;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2249(अ), तारीख 12 जून, 2024 द्वारा 28 जून, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला उद्योग में लगी सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 28 दिसम्बर 2024 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/2018-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2024

S.O. 5364(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Coal industry, which is covered under item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th June, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2249(E), dated the 12th June, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Coal Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 28th December, 2024.

[F. No. S-11017/3/2018-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.11 19:51:03 +05'30'